EDUZONE: International Peer Reviewed/Refereed Multidisciplinary Journal (EIPRMJ), ISSN: 2319-5045
Volume 13, Issue 2, July-December, 2024, Available online at: www.eduzonejournal.com

रोहतक नगर की मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं के विकास का एक अध्ययन

गायत्री[1], डॉ. प्रदीप कुमार शर्मा[2]

[1]शोधार्थी, भूगोल, सामाजिक विज्ञान विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर– 124021, रोहतक (हरियाणा)
[2]एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल, सामाजिक विज्ञान विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर– 124021, रोहतक (हरियाणा)

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन में हरियाणा के रोहतक नगर की मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के परिणामों की जांच का प्रयास किया गया है जिसमें आवास की स्थिति, बुनियादी सेवाओं तक पहुंच और मलिन बस्तियों के निवासियों की सामाजिक–आर्थिक भलाई पर ध्यान केंद्रित किया गया है। काठ मंडी, प्रेम नगर और शिवाजी कॉलोनी आदि के बाहरी क्षेत्रों में उन मलिन बस्तियों के कुल 182 उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण किया गया जहां आधारभूत सुविधाओं का विकास हुआ है। परिणामस्वरूप कई निवासियों के लिए आवास और आधारभूत सुविधाओं में सुधार दिखाई दिया है, लेकिन आर्थिक अस्थिरता, विस्थापन के लिए अपर्याप्त मुआवजा और आधारभूत विकास की गति से असंतोष जैसी चुनौतियों को भी उजागर करता है। आवास की गुणवत्ता में सुधार, परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाना और भविष्य की परियोजनाओं में आर्थिक सहायता और सामुदायिक भागीदारी को शामिल करना आदि सुझाव शामिल हैं।

मुख्य शब्द:- आधारभूत विकास, आवास, गुणवत्ता, आर्थिक स्थिरता, परियोजनाएं।

परिचय:-

भारत में नगरीकरण ने महत्वपूर्ण सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों को जन्म दिया है जिसके साथ अक्सर अनौपचारिक बस्तियों या मलिन बस्तियों का उदय होता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में स्थित रोहतक नगर में तेजी से नगरीय विकास हुआ है जिसके कारण मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। रोजगार की संभावनाओं से आकर्षित होकर ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवासी अक्सर किफायती आवास विकल्पों की कमी के कारण इन अनौपचारिक आवास क्षेत्रों में बस जाते हैं। सरकार ने इन मुद्दों को संबोधित करने और शहरी गरीबों की जीवन स्थितियों में सुधार करने के लिए मलिन बस्तियों के विकास की परियोजनाओं को लागू किया है। इस शोधकार्य का उद्देश्य आवास की स्थिति में परिवर्तन, आधारभूत सुविधाओं और मलिन बस्तियों के निवासियों की आर्थिक स्थिरता का मूल्यांकन करके रोहतक में मलिन बस्तियों में आधारभूत विकास के प्रयासों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना है। इस शोध में निवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों का भी पता लगाया गया है और भविष्य की परियोजनाओं के लिए सुधार के सुझाव दिए गए हैं।

साहित्य समीक्षा :–

नगरीय अध्ययनों और विकास साहित्य में मलिन बस्तियों के आधारभूत विकास का अध्ययन अच्छी तरह से प्रलेखित है। डेविस (2006), जैसे शोधकर्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि अनौपचारिक बस्तियाँ तेजी से नगरीकरण का एक उपोत्पाद हैं, खासकर विकासशील देशों में जहाँ औपचारिक आवास बाजार मांग के साथ तालमेल रखने में विफल रहते हैं। नगरीय सिद्धांतकारों ने लंबे समय से तर्क दिया है कि मलिन बस्तियों का अस्तित्व प्रणालीगत असमानताओं का संकेत है जहां नगरों के भीतर गरीबों को स्थानिक और आर्थिक दोनों तरह से हाशिए पर रखा जाता है (हार्वे, 2008)। भारत में, मलिन बस्तियों के आधारभूत विकास का इतिहास 1950 और 1960 के दशक का है जिसमें आवास प्रावधान और नगरीय बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से मलिन बस्तियों के निवासियों की जीवन स्थितियों में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया था (राव, 2013)।

सन् 2015 में प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की शुरूआत ने इन प्रयासों को और अधिक संस्थागत बना दिया जिसका लक्ष्य सन् 2022 तक सभी शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास प्रदान करना था (आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, 2017)। पीएमएवाई और ऐसे अन्य कार्यक्रमों ने मलिन बस्तियों के विकास, और समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नए आवास समाधान प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया है। हालाँकि, वैश्विक स्तर पर और भारत में मलिन बस्तियों के पुनर्विकास कार्यक्रमों से जुड़ी उल्लेखनीय चुनौतियाँ हैं। रॉय (2009), ने अपने अध्ययन में मलिन बस्तियों के आधारभूत विकास के विस्थापन प्रभावों को उजागर करते हैं जहाँ मलिन बस्तियों के निवासियों को अक्सर उनकी आजीविका के स्रोतों से दूर स्थानांतरित कर दिया जाता है जिससे सामाजिक संपर्क बाधित होते हैं और आर्थिक असुरक्षा में योगदान होता है। इसके अलावा, देसाई (2016), ने उल्लेख किया कि कई मलिन बस्तियों में आधारभूत विकास प्रयासों में प्रभावित सभी समुदायों को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया जाता जिससे मलिन बस्तियों के निवासियों में विकास प्रयासों के प्रति धीरे–धीरे असंतोष और विरोध उत्पन्न होने लगता है। भूमि स्वामित्व और पट्टे की सुरक्षा भी इन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण बाधाएँ उत्पन्न करती हैं, क्योंकि कई मलिन बस्तियों के निवासियों के पास औपचारिक भूमि के शीर्षक नहीं होते हैं जिससे वे कुछ आवास योजनाओं के लिए अयोग्य हो जाते हैं (भान, 2016)।

अध्ययन क्षेत्र :–

हरियाणा के पुराने नगरों में से एक रोहतक है, रोहतक जिले के प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में कार्य करता है और राज्य में एक महत्वपूर्ण नगरीय केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। नई दिल्ली से लगभग 70 किलोमीटर उत्तर–पश्चिम में स्थित, रोहतक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) का हिस्सा है जिसने हाल के दशकों में अपने तेज नगरीकरण को उत्प्रेरित किया है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार 400,000 से अधिक की जनसंख्या के साथ, रोहतक में ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों की पर्याप्त आमद देखी गई है जिसने आर्थिक विकास और अनौपचारिक बस्तियों के विकास में योगदान दिया है जिन्हें आमतौर पर मलिन बस्तियों के रूप में जाना जाता है।

रोहतक में नगरीय विकास और मलिन बस्तियों का निर्माण :–

नगर की स्थिति और बढ़ते औद्योगिक और वाणिज्यिक अवसरों ने इसे प्रवासी श्रमिकों और आर्थिक रूप से वंचित जनसंख्या के लिए एक आकर्षण बना दिया है। हालाँकि, इस तेज नगरीकरण ने रोहतक के नगरीय इलाकों में और उसके किनारों पर मलिन बस्तियों के प्रसार को जन्म दिया है।

इन मलिन बस्तियों की विशेषता भीड़भाड़ वाले आवास, स्वच्छ पानी, स्वच्छता और बिजली जैसी सुविधाओं की कमी और खराब बुनियादी ढाँचा है। रोहतक में मलिन बस्तियों का विस्तार भारत में नगरीय विकास की व्यापक चुनौतियों को दर्शाता है जहाँ आर्थिक अवसर अक्सर कम आय वाली जनसंख्या के लिए पर्याप्त आवास और सेवाएँ प्रदान करने की क्षमता से आगे निकल जाते हैं।

सरकारी पहल और मलिन बस्तियों में आधारभूत विकास :–

बढ़ती मलिन बस्तियों की जनसंख्या के जवाब में, केंद्र और राज्य सरकारों ने रोहतक में मलिन बस्तियों में आधारभूत विकास और पुनर्वास के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों को लागू किया है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) शामिल है जो सन् 2022 तक सभी शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखती थी, और स्थानीय शहरी नवीनीकरण पहल जो मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए बुनियादी ढाँचे, आवास और आधारभूत सेवाओं तक पहुँच में सुधार पर ध्यान केंद्रित करती है।

इन प्रयासों के बावजूद, सार्थक और समावेशी आधारभूत विकास को प्राप्त करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं, कई मलिन बस्तियों के निवासियों को विस्थापन, अपर्याप्त मुआवजे और उचित आजीविका समर्थन की कमी से संबंधित मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है।

कार्यप्रणाली:–

इस शोधकार्य को पूर्ण करने के लिए रोहतक नगर के उन क्षेत्रों का प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया जिनमें आधारभूत सेवाओं के विकास संबधित कार्यों के प्रयास किए गए हैं जिसमें काठ मंडी, प्रेम नगर और शिवाजी

कॉलोनी शामिल हैं। सर्वेक्षण के दौरान आंकड़े एकत्रित करने के लिए कुल 182 प्रश्नावली मलिन बस्तियों के निवासियों की मदद से भरवाई गई जिन्होंने आधारभूत विकास के प्रभावों का अनुभव किया था। सर्वेक्षण में आवास की स्थिति, बुनियादी सेवाएं, आय में परिवर्तन, सामाजिक संबंध और आधारभूत विकास में सरकार की भूमिका से संतुष्टि पर सवाल शामिल थे। निवासियों के जीवन की गुणवत्ता पर विकास के प्रभाव का आकलन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

अध्ययन के लिए चयनित मलिन बस्तियों के क्षेत्र :
इस शोध में रोहतक नगर की 3 चयनित मलिन बस्तियों के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जहाँ मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं के विकास की परियोजनाएँ शुरू की गई हैं। ये क्षेत्र रोहतक की मलिन बस्तियों के एक क्रॉस–सेक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी चुनौतियाँ और विशेषताएँ हैं:

i. **काठ मंडी मलिन बस्ती :** नगर के वाणिज्यिक केंद्र के पास स्थित, इन मलिन बस्ती को सरकारी आवास योजनाओं के तहत विकास के लिए लक्षित किया गया है। यह एक ऐसा मामला प्रस्तुत करता है जहाँ निवासियों के पास बुनियादी ढाँचे और आवास की गुणवत्ता में सुधार के बारे में मिश्रित अनुभव हैं।
ii. **प्रेम नगर मलिन बस्ती :** नगर के बाहरी इलाके में एक घनी आबादी वाला क्षेत्र, प्रेम नगर ने प्रवास के कारण तेजी से विकास का अनुभव किया है। यहाँ विकास के प्रयास बेहतर स्वच्छता और जल आपूर्ति प्रदान करने पर केंद्रित हैं, हालाँकि महत्वपूर्ण अंतराल अभी भी बने हुए हैं।
iii. **शिवाजी कॉलोनी मलिन बस्ती :** एक और बड़ी अनौपचारिक बस्ती, शिवाजी कॉलोनी का टुकड़ों में विकास किया गया है। यह क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक रूप से विविध जनसंख्या में सरकारी कार्यक्रमों को लागू करने की चुनौतियों को उजागर करता है।

परिणाम :–

तालिका 1: ***मलिन बस्तियों में आधारभूत विकास***

क्र.सं.	पूछे गए प्रश्न	प्रतिक्रिया के प्रकार	उत्तरदाताओं की संख्या
1.	आधारभूत विकास के बाद आवास की स्थिति	बहुत सुधार हुआ	96
		थोड़ा सुधार हुआ	40
		कोई बदलाव नहीं	46
		पहले से बदतर	0
2.	क्या वे नए आवास ढांचे संरचनात्मक रूप से मजबूत, सुरक्षित और दीर्घकालिक निवास के लिए उपयुक्त हैं?	हाँ	146
		नहीं	36
3.	क्या आधारभूत विकास योजना में पर्याप्त वायु संचालन, स्वच्छता और गोपनीयता शामिल है?	हाँ	125
		नहीं	57
4.	आधारभूत विकास के प्रयासों में स्थानीय पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हरित स्थान, पेड़ या भूनिर्माण शामिल हैं।	हाँ	63
		नहीं	119
5.	निम्नलिखित आधारभूत सेवाएँ	स्वच्छ पेयजल	158
		बिजली	167
		उचित स्वच्छता (शौचालय,	148

		सीवेज)	
		स्वास्थ्य सुविधाएँ	138
		अपशिष्ट संग्रह सेवाएँ	155
		बच्चों के लिए स्कूल	158
6.	आधारभूत विकास कार्यक्रम के बाद आपके जीवन की समग्र गुणवत्ता में क्या बदलाव आया है?	बहुत सुधार हुआ	86
		थोड़ा सुधार हुआ	34
		कोई बदलाव नहीं	46
		बिगड़ गया	16
7.	क्या आपके क्षेत्र के आधारभूत विकास के बाद आपकी आय में बदलाव आया है?	वृद्धि हुई	31
		कमी हुई	55
		कोई बदलाव नहीं	96
8.	क्या आप आधारभूत विकास के बाद आर्थिक रूप से अधिक स्थिर महसूस करते हैं?	हाँ	78
		नहीं	56
		अनिश्चित	48
9.	आधारभूत विकास ने पड़ोसियों और समुदाय के साथ आपके सामाजिक संबंधों को कैसे प्रभावित किया है?	सुधार	47
		वही रहा	112
		बिगड़ा	23
10.	मलिन बस्तियों में आधारभूत विकास और पुनर्वास में सरकार की भूमिका से आप कितने संतुष्ट हैं?	बहुत संतुष्ट	21
		संतुष्ट	26
		तटस्थ	54
		असंतुष्ट	45
		बहुत असंतुष्ट	36

स्रोतः शोधार्थी द्वारा प्राथमिक सर्वेक्षण के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़े

आवास की स्थिति :

उपर्युक्त तालिका के अनुसार 182 उत्तरदाताओं में से, 52.7 **प्रतिशत** ने बताया कि उनके आवास की स्थिति में काफी सुधार हुआ है, जबकि 22 **प्रतिशत** ने मामूली सुधार का संकेत दिया, और 25.3 **प्रतिशत** ने कोई बदलाव नहीं देखा। उत्तरदाताओं में से किसी ने भी नहीं बताया कि उनके आवास की स्थिति खराब हुई है। नए आवास की संरचनात्मक मजबूती के संदर्भ में, 80 **प्रतिशत** ने महसूस किया कि इमारतें मजबूत हैं और दीर्घकालिक निवास के लिए उपयुक्त हैं। हालाँकि, 20 **प्रतिशत** ने संरचनात्मक गुणवत्ता के बारे में चिंता जताई। पर्याप्त वायु संचालन, स्वच्छता और गोपनीयता को महत्वपूर्ण पहलुओं के रूप में देखा गया। जबकि 68.7 **प्रतिशत** उत्तरदाताओं का मानना है कि इन्हें पर्याप्त रूप से शामिल किया गया है, 31.3 **प्रतिशत** ने महसूस किया कि आधारभूत विकास योजना में इन आवश्यक तत्वों की कमी है।

आधारभूत सेवाएं :

सर्वेक्षण के आधार पर ज्ञात होता है कि मलिन बस्तियों में आधारभूत विकास से महत्वपूर्ण सुधार हुआ हैः

- **i.** स्वच्छ पेयजलः 86.8 **प्रतिशत** ने स्वच्छ पेयजल पहुँचने की सूचना दी।
- **ii.** बिजलीः 91.8 **प्रतिशत** उत्तरदाताओं ने बताया की बिजली की नियमित पहुँच है।
- **iii.** उचित स्वच्छताः 81.3 **प्रतिशत** ने कार्यशील शौचालयों और सीवेज सिस्टम तक पहुँच की सूचना दी।
- **iv.** स्वास्थ्य सुविधाएँः 75.8 **प्रतिशत** लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हुई।
- **v.** अपशिष्ट संग्रहः 85.1 **प्रतिशत** ने अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार की सूचना दी।
- **vi.** बच्चों के लिए स्कूलः 86.8 **प्रतिशत** ने बेहतर शिक्षा की सूचना दी।

इन सुधारों के बावजूद, 65.4 **प्रतिशत** उत्तरदाताओं ने कहा कि आधारभूत विकास प्रयासों में हरित स्थान या पर्यावरणीय सुधार शामिल नहीं थे, जो टिकाऊ शहरी नियोजन पर ध्यान केंद्रित न होने का सुझाव देता है।

आर्थिक प्रभाव :

रोहतक नगर की मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के आर्थिक प्रभाव मिश्रित हैं। 17 **प्रतिशत** उत्तरदाताओं ने आय में वृद्धि की सूचना दी जबकि 30.2 **प्रतिशत** ने कहा कि उनकी आय में कमी आई है।

शेष 52.7 **प्रतिशत** ने कोई बदलाव नहीं देखा। इसके अतिरिक्त, 42.9 **प्रतिशत** उत्तरदाताओं ने विकास के बाद आर्थिक रूप से अधिक स्थिर महसूस किया, जबकि 30.8 **प्रतिशत** ने स्थिर महसूस नहीं किया और 26.4 **प्रतिशत** अनिश्चित हैं।

सामाजिक संबंध और सामुदायिक सामंजस्य :

मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं के विकास से सामाजिक संबंध काफी हद तक अप्रभावित रहे, 61.5 **प्रतिशत** ने कोई बदलाव नहीं देखा। 25.8 **प्रतिशत** उत्तरदाताओं ने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंधों का संकेत दिया जबकि 12.6 **प्रतिशत** ने सामाजिक संबंधों में गिरावट की सूचना दी। सर्वेक्षण सामुदायिक व्यवधान को कम करने के लिए विकास प्रक्रिया के दौरान सामाजिक सामंजस्य बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

सरकार की भूमिका से संतुष्टि :

मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं के विकास में सरकार की भूमिका से संतुष्टि कम है। केवल 11.5 **प्रतिशत** बहुत संतुष्ट है और 14.3 **प्रतिशत** संतुष्ट है, जबकि 44.5 **प्रतिशत** ने असंतोष या तीव्र असंतोष व्यक्त किया। यह विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर पारदर्शिता और संचार की आवश्यकता को दर्शाता है।

निष्कर्ष

रोहतक में मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं के विकास ने कई निवासियों के लिए आवास की गुणवत्ता और आवश्यक सेवाओं में सकारात्मक बदलाव किए हैं। हालाँकि, आर्थिक अस्थिरता, सरकारी प्रयासों से असंतोष और हरित क्षेत्रों की अनुपस्थिति जैसी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। भविष्य की परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन करना, आवास की गुणवत्ता में सुधार और आजीविका बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता कार्यक्रम प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इन पहलों की दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए विकास प्रक्रिया में अधिक से अधिक सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है।

संदर्भ सूची

[1]. डेविस, एम. (2006). *प्लेनेट ऑफ स्लम्स.* वर्सो।

[2]. देसाई, आर. (2016). *भारत में शहरी नवीनीकरणः नीतियाँ, राजनीति और राज्य.* रूटलेज।

[3]. रॉय, ए. (2009). नागरिक शासनः बेरूत और मुंबई में समावेश की राजनीति. *एंटीपोड, 41(1),* 159–179.

[4]. यूएन–हैबिटेट. (2015). *झुग्गियों की चुनौतीः मानव बस्तियों पर वैश्विक रिपोर्ट.* अर्थस्कैन।

[5]. भान, जी. (2016). *जनता के हित में: समकालीन दिल्ली में बेदखली, नागरिकता और असमानता.* जॉर्जिया प्रेस विश्वविद्यालय।

[6]. देसाई, आर. (2016). शहरी गरीबों पर शासनः रिवरफ्रंट विकास, झुग्गी पुनर्वास और अहमदाबाद में समावेश की राजनीति. *आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 51(2),* 67–77.

[7]. हार्वे, डी. (2008). *द राइट टू द सिटी.* न्यू लेफ्ट रिव्यू, 53, 23–40.

[8]. आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय. (2017). *प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – सभी के लिए आवास.* भारत सरकार।

[9]. राव, पी. वी. (2013). मलिन बस्तियों के पुनर्विकासः भारत का अध्ययन. *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अर्बन एंड रीजनल रिसर्च, 37(4),* 1354–1372.

[10]. रॉय, ए. (2009). भारत अपने शहरों की योजना क्यों नहीं बना सकताः अनौपचारिकता, विद्रोह और शहरीकरण का मुहावरा. *प्लानिंग थ्योरी, 8(1),* 76–87.